

देश के हर नगर व ग्रामांचल में

दैनिक निर्दलीय को प्रतिनिधि चाहिए

पत्रकारिता के साथ सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक-अभिरुचि वालों को प्राथमिकता।

संपर्क करें- 91 8839797448/942443401

निर्दलीय प्रकाशन

फ ११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल ४६२ ०१६

निर्दलीय प्रकाशन का स्वर्ण जयंती वर्ष

संपर्क-फ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल

प्रस पंजीयन एम.पी.एच.आई.एन./२०११/४८५६५

निष्पक्षता, निर्वैरता व निर्भयता का दैनिक प्रवक्ता

ई-मेल: nirdaliyadaily@gmail.com

दैनिक निर्दलीय साप्ताहिक निर्दलीय और मासिक निर्दलीय अब तीनों स्वरूपों में वेबसाइट www.nirdaliya.com पर उपलब्ध विधि: पहले उबत लिंक पर जाएं फिर क्लिक करें e-paper, इसके बाद थंबक निर्दलीय जिस तारीख का पढ़ना हो वह तारीख और एच संख्या डालें। साप्ताहिक हेतु weekly निर्दलीय और मासिक हेतु Magazine निर्दलीय क्लिक करें निर्दलीय एफ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२०१६

वर्ष-५४/१६ अंक- ६६

भोपाल, १३ सितंबर, डाक १४ सितंबर २०२६

भोपाल व नई दिल्ली से प्रकाशित

पृष्ठ -८

मूल्य १+१/- (संप्रेषण/स्वैच्छिक)

झोलावालों’ से ‘दिमागी नक्सल’ तक

1970 का दशक भारत के लिए राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता का दौर था। इसके बावजूद, वह एक ऐसा समय था जब व्यवस्था के टकरावों को लोकतंत्र की जीवन-रेखा माना जाता था, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई संकट। मैं यह बात पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस इतिहास का महज गवाह नहीं रहा, बल्कि मैंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है।

जब भारत के ‘दूधवाले’ यानी ‘आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड’ (अमूल) के महाप्रबंधक डॉ. वर्गीज कुरियन कायरा जिले के दुग्ध-उत्पादक किसानों की सामाजिक-आर्थिक हकीकत का नक्शा तैयार कर रहे थे, ताकि फिल्मकार श्याम बेनेगल उस पर फिल्म बना सकें, तब मैं उनके साथ काम कर रहा था।

बाद में, मैं मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में ‘विज्ञान शिक्षण’ से जुड़ी स्वयंसेवी संस्था किशोर भारती से जुड़ा। यहाँ हम बेहद आदर्शवादी और जुनूनी लोगों की एक टीम थे, जिसका नेतृत्व ‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ (टीआईएफआर) जैसी प्रतिष्ठित संस्था को छोड़कर आए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉ. अनिल सद्गोपाल कर रहे थे।

हम एक ऐसे देश के नागरिक थे जो अपने ही दिमाग से, अपनी सोच से डरा हुआ नहीं था। हमने निस्वार्थ भाव से ग्रामीण युवाओं को खोज-आधारित विज्ञान के चमत्कारों से रूबरू कराया और उन्हें प्रयोगों को आकार देने के लिए सवाल (सवाल ही राम) पूछना सिखाया।

आज, जो लोग सवाल पूछते हैं, उन्हें डराया-धमकाया जाता है; उन्हें अलग-थलग करने और खत्म करने की धमकियाँ दी जाती हैं। इसके बावजूद, इस चुनौती को जेन-जी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) जैसे छत्र संगठनों ने बड़ी बहादुरी से स्वीकार किया है।

जंतर-मंतर पर प्रतिरोध के जिस अवज्ञा उत्सव ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, उसका समापन केंद्रीय शिक्षामंत्री के इस्तीफे के साथ हुआ। इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके इस घटनाक्रम को वरिष्ठ पत्रकार हरीश खरे ने 21 जुलाई के द वायर में रेखांकित किया है - ‘20 जुलाई को लक्ष्मण रेखा पार कर ली गई।’

इसके बाद से राजनीतिक रंगमंच ने अगस्त के महीने में बयानबाजी का एक और खौफनाक दौर देखा और देश के शब्दकोश में एक नया, डरावना मुहावरा शामिल हो गया - ‘दिमागी नक्सल।’ राय ने अब अपना

स्वतंत्रता आंदोलन से अभी हाल तक हमारे यहां गैर-दलीय राजनीति की खासी हवा चली थी। इस दौर में तमाम बातों के अलावा अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना सिखाया जाता था। धीरे-धीरे सवाल उठाना न सिर्फ अपराध होता गया, बल्कि सवाल उठाने वालों को ‘दिमागी नक्सल’ तक कहा जाने लगा। क्या मौजूदा निजाम की यह हरकत हमारे युवा दिमागों को भोंथरा नहीं बना रही है? क्या प्रश्नहीन दिमाग ‘भक्त’ बनाने, बनाए रखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होते? अपने तब, विविध अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं, विवेक पिंटो। सं.

युद्धक्षेत्र मध्य भारत के भौतिक जंगलों से हटाकर मानव चेतना और मस्तिष्क के आंतरिक ढांचे के भीतर स्थानांतरित कर दिया है।

1970 के दशक में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम (एचएसटीपी) द्वारा बनाए गए पोस्टकार्ड वाले मासूम शैक्षिक ‘शुभंकरों’ से लेकर आज राय-प्रायोजित विचार-शिकार (माइंड-हंट्स) तक की यह यात्रा, दरअसल स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक पूछताछ के व्यवस्थित अपराधीकरण की कहानी है। कल तक जिस झोलावाले के आदर्शवाद को एक सहज रूप में देखा जाता था, आज उसी झोले को राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक खतरे के रूप में पेश कर कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है।

भारतीय लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा इस मामले में किस हद तक सड़ चुका है, इसे समझने के लिए मैं सवाल पूछने की उसी जन्मभूमि यानी ‘एचएसटीपी’ की ओर लौटता हूँ। ‘किशोर भारती’ की टीम का मिशन एक संज्ञानात्मक संस्कृति (कॉग्निटिव कल्चर) को विकसित करना था, न कि किसी तख्तापलट या विद्रोह को। हमने रटने और समर्पण करने वाली गुलामी की जगह एक ‘वैज्ञानिक मिजाज’ को स्थापित किया था।

इस शैक्षणिक बगावत के केंद्र में सवालीराम नाम का एक काल्पनिक चरित्र था, जिसे बचे बाल वैज्ञानिक (1972-2002) के तहत अपनी इछा से कोई भी सवाल पूछते हुए पोस्टकार्ड लिखते थे। यह ‘वर्कबुक’ (कार्यपुस्तिका) कक्षाओं से मिले अनुभवों के आलोक में टीम द्वारा लगातार संपादित की जाती थी। शुरुआती दौर में इसमें प्रायोगिक भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल थे, बाद में हाईस्कूल के लिए भौतिकी, रसायन, व्यावहारिक गणित और यामिति को भी जोड़ा गया।

यह बात स्वतः स्पष्ट थी कि विज्ञान पढ़ाने के इस खोज-आधारित दृष्टिकोण में सवाल पूछना अनिवार्य था, क्योंकि ‘सब कुछ पहले से तय नहीं था।’ ‘एचएसटीपी’ ने सवालीराम की कल्पना ‘राम’ के रूप में की थी - जो बौद्धिक झोलावाले का एक बेहद

आत्मीय और मित्रवत अवतार था।

सुरील जोशी अपनी किताब जश्न-ए-तालीम (एकलव्य, 2008) में लिखते हैं, ‘सवालीराम के पास आने वाले सवालों की समीक्षा करें, तो वे वर्कबुक की सीमाओं से लेकर बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों तक फैले हुए थे।’

इसलिए, एक ग्रामीण छात्र टीम को पत्र लिखकर यह पूछ सकता था कि गाँव के कुएं पर स्थानीय सवर्ण जमींदार का ही नियंत्रण क्यों है, या पारंपरिक पूजा-पाठ के बावजूद फसल क्यों बर्बाद हो गई? और उसे जवाब में किसी पाठ्यपुस्तकीय रूढ़िवादिता या घुड़की का सामना नहीं करना पड़ता था।

इस तरह, स्कूली बच्चों को सत्ता और प्रकृति का खुद विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक अवलोकन के औजार मिले। हमारी टीम के सदस्यों के झोले टेस्ट ट्यूब, चुंबक, लेंस और पोस्टकार्डों से भरे होते थे - वे एक वैकल्पिक राष्ट्र-निर्माण के प्रतीक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय का राय पूछताछ और प्रयोग को राजद्रोह नहीं मानता था; बल्कि वह इसके लिए धन देता था।

‘अमूल’ में इसी कड़े और सुधारात्मक टकराव के मिजाज ने आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया था। कुरियन और उनके समूह ने श्याम बेनेगल के साथ बैठकर इस जमीनी और कचे सामाजिक टकराव को पर्दे पर उतारने की चर्चा की। नतीजतन, 1976 में फिल्म मंथन का जन्म हुआ। गिरीश कर्नाड ने पशु चिकित्सक डॉ. मनोहर राव के रूप में पर्दे पर कदम रखा और वास्तविक दुनिया के सामने एक शक्तिशाली सिनेमाई आईना पेश किया कि कैसे ‘डेयरी उद्योग सामाजिक-आर्थिक बदलाव का एक साधन है।’

डॉ. राव एक मुकम्मल झोलावाले थे। वह कायरा जिले के एक गांव में ढलती शाम के वक्त पहुंचे थे, उनके पास कंधे पर लटके एक कपड़े के बैग (झोले), दूध-विश्लेषक (मिल्क एनालाइजर), बही-खाते और एक पशु चिकित्सा किट के अलावा कुछ नहीं था। खतरा, यदि कोई था, तो वह पूरी तरह से व्यवस्था और यथास्थिति के लिए था।

बाधाओं को तोड़कर हाशिए पर पड़े, निचली जाति के दुग्ध उत्पादक किसानों को सामंती अभिजात वर्ग के साथ ही दिन में दो बार एक ही कतार में खड़ा होना पड़ता था।

उस दौर से लेकर 2026 के समकालीन परिदृश्य तक का संक्रमण राय और नागरिक के बीच के संबंधों का पूरी तरह उलट जाना है। आज राय अपनी विफलताओं को छिपाने और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मानसिक और वैचारिक स्पेस के लिए सीधे खतरे के रूप में ब्रांड करके उनका दमन कर रहा है। राय की नीतियों की एक स्वतंत्र, व्यवस्थागत आलोचना करना अब एक स्वस्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेत नहीं माना जाता। इसके विपरीत, ‘दिमागी नक्सल’ के बैनर तले खुद बुद्धि और विवेक को ही एक बीमारी कारर दे दिया गया है।

परम पाखंड यह है कि जहाँ 1976 के मंथन ने हाशिए के लोगों को मुक्त करने के लिए दूध का मंथन किया था, वहीं इस शासन ने एक अलग तरह का मंथन शुरू किया है-एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुकूलन (कंडीशनिंग) जिसका उद्देश्य शुद्ध, बिना किसी सवाल वाली भक्ति पैदा करना है।

इस वैचारिक और शाब्दिक बदलाव का एकमात्र उद्देश्य देश को दो धड़ों में बांटना है-एक तरफ वे दिमागी नक्सल जिन्हें विश्लेषण करने की ज़रूरत के कारण अपराधी बना दिया गया है, और दूसरी तरफ वे भक्त जो बिना सोचे-समझे कॉर्पोरेट और राजनीतिक ‘ज़ोंबी’ में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ तालियाँ बजाने की ट्रेनिंग दी गई है।

कुरियन, उनके समूह और ‘किशोर भारती’ की टीम के साथ काम करते हुए मैंने करीब से देखा है कि वास्तविक राष्ट्र-निर्माण कैसा होता है। यह हर तरह के खतरनाक सवाल पूछने वाले पोस्टकार्डों से भरा हुआ एक कमरा होता है; यह जातिगत दीवारों और पितृसत्ता से मुक्त दूध की एक कतार होती है। आज, छात्रों से कहा जा रहा है कि वे अपनी जिज्ञासा का सौदा कायरता और चाटुकारिता से कर लें।

इसके बावजूद, अपने कंधों पर झोला लटकाए लाखों जिंदादिल सवालीराम देश भर की सड़कों पर उतर चुके हैं। वे छात्रों के साथ मिलकर अपने जर्जर स्कूलों और नदारद शिक्षकों के लिए जवाबदेही मांग रहे हैं-और ऐसा करते हुए वे लाठियों, पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और पैलेटगन का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। (सप्रेम)

जे.के.स्टील फर्नीचर

भोपाल

जीवन मारण

स्वत्वाधिकारी संपर्क-9826422823

१. पेट्रोल पंप के सामने,चूना भट्टी, कोलार मुख्य मार्ग, २. सर्वधर्म कॉलोनी सी सेक्टर पुल समीप कोलार मुख्य मार्ग, ३. बरखेड़ी कलां मुख्य मार्ग, भोपाल

पिछले कुछ सालों में युवाओं के कई आंदोलन हुए हैं, विशेषकर जेन जी पीढ़ी की अगुआई में, जिन्होंने सरकारों को गिरा दिया या राजनीतिक माहौल को नाटकीय ढंग से बदल दिया। नेपाल, बांग्लादेश, मेडागास्कर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मोरक्को और दूसरी जगहों पर लगातार विरोध-प्रदर्शनों ने सरकारों को भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया या उन्हें सत्ता से ही हटा दिया, लेकिन क्या इन सभी से न्याय की दिशा में कोई बुनियादी बदलाव आया? इसका एक नया रूप भारत में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) है जिसका अचानक सामने आना उतना ही चौंकाने वाला था, जितना कि ड्रेनपाइप से कॉकरोच का निकलना।

बेशक, युवा आंदोलन सिर्फ जेन जी की देन नहीं हैं। हाल के उदाहरणों में वर्ष 2010-11 में अरब क्षेत्र में हुए विद्रोह (जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है) शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई जगह सत्ता परिवर्तन हुआ। 1968 में दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर चला, जिनमें से कई का नेतृत्व युवाओं ने किया। ये विरोध युद्ध, नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों, मजदूरों के अधिकारों, तानाशाही-विरोधी और अन्य मुद्दों पर थे। मेरा खुद का सफ़र 1980 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के शहरी जंगलों को बचाने और ऐसे विकास के खिलाफ स्कूल और कॉलेज के छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन से शुरू हुआ, जिस 'विकास' को हमने प्रकृति के बेरहम विनाश और प्रकृति पर निर्भर समुदायों के विस्थापन के कारण विनाश का नाम दिया था।

इनमें से कई आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्यों को हासिल करने में कुछ हद तक सफल रहे हैं, जैसे किसी जंगल को बचाना या किसी सरकार को गिराना, लेकिन ज्यादातर मामलों में इनसे व्यवस्था में बुनियादी बदलाव नहीं आया। राजनीतिक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित रही, उसमें बने रहने के लिए आदर्शों और मूल्यों से समझौता किया जाता रहा और आर्थिक मॉडल औद्योगीकरण और कभी न खत्म होने वाली आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित रहा। यह मॉडल जितने रोजगार पैदा करता है, उतने ही खत्म भी कर देता है, साथ ही हमें वैश्विक पारिस्थितिकीय पतन की ओर भी धकेलता है।

1960 और 70 के दशक में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोहों से मजदूरों को अधिकार मिलने जैसे कई फायदे हुए, लेकिन इनसे पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण और देशों के बीच कड़े मुकाबले (या युद्ध) के हालात नहीं बदले। नतीजे में इंसानियत के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं – जैसे भयानक गैर-बराबरी, पर्यावरण का विनाश, युद्ध और नरसंहार,

'जेन जी' के लिए कुछ हिदायतें

इन दिनों देशभर के युवाओं यानि 'जेन जी' ने भारी उथल-पुथल मचा रखी है। कई छोटे-बड़े मसलों पर उन्हें और उनसे आगे की 'जेन अल्फा' पीढ़ियों को सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन क्या ये सफलताएं कोई ठोस, स्थायी बदलाव ला सकेगी? पड़ोसी देश नेपाल में, जहां 'जेन जी' के आंदोलन के कारण पिछले साल सत्ता बदली थी, प्रचलित 'विकास' में कोई बदलाव नहीं आया। नतीजे में लकीर की फकीर सत्ताधारी 'जेन जी' पीढ़ी आज भीषण प्राकृतिक आपदा भुगत रही है। आखिर राजनीतिक, आर्थिक बदलाव के बाद में उनसे देश क्या उम्मीदें बांधें? अपने इस लेख में बता रहे हैं, अशीष कोठारी। सं.

तानाशाही और लोकतांत्रिक अधिकारों का कमजोर होना आदि – को हल करने के लक्ष्य अभी भी दूर के सपने ही हैं।

हमें यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा कि क्या नेपाल का नया राजनीतिक नेतृत्व ऐसे बुनियादी बदलाव ला पाएगा। 36 साल के इंजीनियर-रैपर बालेन्द्र शाह की अगुआई वाली सरकार ने सुधारों का एक बड़ा 100-सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। इसमें कल्याणकारी कामों और जवाबदेह व कुशल शासन के कई अच्छे कदम शामिल हैं, लेकिन विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के लिए गांव और शहर के समुदायों को मजबूत करने के बारे में इसमें कुछ नहीं दिखता। नेपाल को पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ बनाने की दिशा में भी इसमें बहुत कम बातें दिखीं।

इस एजेंडा के कुछ बिंदु बेहद विनाशकारी भी हो सकते हैं, जैसे 'ऊर्जा निर्यात से ज्यादा-से-ज्यादा कमाई करने और जलविद्युत विकास को तेज करने' की योजना। अगर इनमें पहाड़ी इलाकों की ऐसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हों, जिनके गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक नतीजे हो सकते हैं तो बात क्रांति के उलट हो सकती है। खबरों के मुताबिक, नेपाल में राजनीतिक बदलाव लाने वाले जेन जी आंदोलन' के लोग इस मामले पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सरकार में शामिल हैं और कुछ ज़मीनी लोकतंत्र और पारिस्थितिकीय संतुलन को लेकर बहुत सचेत भी हैं।

क्या उनके पास सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोई सोच है, ताकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नज़र रखी जा सके? अगर बेरोजगारी और महंगाई विरोध-प्रदर्शनों की मुख्य वजह रही हैं, तो क्या नए नेताओं के पास सम्मानजनक रोजगार पैदा करने और कीमतों को ऐसे तरीकों से नियंत्रित करने का कोई तरीका है, जो न्यायपूर्ण और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हों? क्या वे औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाले उन्हीं नाकाम मॉडलों या नव-उदारवादी अर्थशास्त्र के उन तत्वों को ही अपनाएंगे, जो

पर्यावरण की सुरक्षा को कोई गंभीर मुद्दा नहीं मानते? इनमें से किसी भी वैकल्पिक रास्ते की कल्पना करना आसान नहीं है, उन्हें लागू करना तो दूर की बात है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं हैं, जैसा कि दुनिया भर में हजारों सफल कोशिशें दिखा रही हैं। समुदायों ने दिखाया है कि पश्चिमी देशों के सतही लोकतंत्र की बजाए असली लोकतंत्र कैसे काम कर सकता है; जहां हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है, फ़ैसले लेने की प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी समुदायों से शुरू होती है और प्रकृति भी ऐसे फ़ैसलों का हिस्सा होती है। मजदूरों के समूहों ने दिखाया है कि जिम्मेदार उत्पादन कैसे किया जा सकता है, जिससे सभी को फ़ायदा हो। किसानों के समूहों ने खाद्य उत्पादन प्रणालियों की विविधता दिखाई है, जो मिट्टी, पानी और उनमें मौजूद सभी जीवों को नष्ट या जहरीला नहीं बनाती।

आंदोलनों को यह तो अच्छी तरह पता होता है कि वे किसके खिलाफ हैं, लेकिन यह कम पता होता है कि वे किसके पक्ष में हैं। बदलाव के लिए उनकी सोच और तरीके अक्सर उसी व्यवस्था के अंदर सुधार तक ही सीमित रहते हैं। मसलन – वे चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के असर को कम करने के लिए चुनाव की नियामक संस्थाओं की आज़ादी की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर यह नहीं पूछते कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए, ताकि जनता सभी संस्थाओं पर नज़र रख सके? या जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन यह सवाल नहीं पूछते कि किस तरह की नवीकरणीय ऊर्जा सचमुच न्यायपूर्ण और टिकाऊ है?

इसके अलावा, वित्तीय भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे काफी गुस्सा और निराशा पैदा होती है। इस बुराई के कारण कई आंदोलन शुरू हुए हैं। भ्रष्टाचार वित्तीय गड़बड़ियों से कहीं बड़ी चीज़ है। सोच-विचार में भी भ्रष्टाचार होता है, जिससे बेतहाशा मुनाफा कमाने की होड़ और सत्ता पर कब्ज़ा बनाए

रखने की बेईमान राजनीति को बढ़ावा मिलता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई वित्तीय भ्रष्टाचार न हो, उसमें भी भारी गैर-बराबरी और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 'सीजेपी' के घोषणापत्र की कुछ मांगें (जैसे मीडिया को कॉरपोरेट नियंत्रण से मुक्त करना) इसी दिशा में इशारा करती हैं, जो उत्साहजनक हैं।

बेरोजगारी आंदोलनों की एक बड़ी वजह है, लेकिन आम तौर पर ये विकास के उस मौजूदा मॉडल को चुनौती नहीं देते, जो लगातार आर्थिक विकास और तकनीक की ऐसी बेलगाम दौड़ पर आधारित है, जिसमें मशीनें इंसानी मेहनत और काम करने की क्षमता की जगह ले लेती हैं। उन्हें इस मॉडल को बदलकर ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है, जो प्रकृति और तकनीक के साथ मिलकर काम करने वाले सम्मानजनक रोज़गार को बढ़ावा दें। भारत जैसे देश में इसका मतलब है – हाथ से बनी चीज़ों, विकेंद्रीकृत और छोटे स्तर के उत्पादन को प्राथमिकता देना; लाखों हेक्टेयर ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाना; विकेंद्रीकृत सेवाएं और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना वगैरह।

शिक्षा के मामले में भी यही बात लागू होती है। हमें शिक्षा के ऐसे नज़रिए की ज़रूरत है, जहां युवा रचनात्मक और मज़ेदार तरीके से सीख सकें; एक-दूसरे और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनें; अपनी पसंद के हुनर और क्षमता को निखार सकें; अपने समुदायों के साथ-साथ दूसरों से भी सीख सकें; दूसरों की संस्कृति और भाषाएं सीखते हुए अपनी पारिवारिक संस्कृति और भाषाओं पर गर्व कर सकें; ऐसे रोज़गार के विकल्प तलाश सकें जो उन्हें सम्मान और आज़ादी दें; गैर-बराबरी को चुनौती दे सकें; और जलवायु व अन्य संकटों का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें।

आज के युवा इन चीज़ों को समझें और उनसे सीखें, इसके लिए अलग-अलग पीढ़ियों के बीच बातचीत और सीखने-सिखाने का माहौल होना चाहिए। 'जेन जी' (और अब 'जेन ए' और उसके बाद जो भी अक्षर आएँ!) के पास बेहतर दुनिया के लिए क्रांति का नेतृत्व करने की खातिर ऊर्जा, नई सोच और रचनात्मकता है, लेकिन इसके लिए, विरोध-प्रदर्शन के साथ-साथ उन बुनियादी बदलावों की झलक भी दिखनी चाहिए, जिनकी पृथ्वी को ज़रूरत है। उम्मीद है कि दुनिया भर में युवा जिन क्रांतियों में शामिल हैं, वे पहले से ही ऐसे नज़रिए पर विचार कर रहे होंगे या करेंगे और सभी उम्र के नागरिक आंदोलन उनके समर्थन और एकजुटता में खड़े होंगे। (संप्रेस)

डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण भविष्य की शिक्षा की नई दिशा निर्धारित

आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म ने शिक्षा के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल शिक्षा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।

डिजिटल शिक्षा ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। अब विद्यार्थी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, वर्चुअल कक्षाओं तथा ऑनलाइन मूल्यांकन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आत्म-अधिगम, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता और डिजिटल साक्षरता जैसे 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों का भी विकास हो रहा है।

भारत सरकार ने अनेक डिजिटल पहलें शुरू कर शिक्षा को अधिक सुलभ एवं समावेशी बनाने का प्रयास किया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने मिश्रित शिक्षण, डिजिटल अवसरचन, बहुभाषी ई-सामग्री तथा शिक्षकों के तकनीकी प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया है।

हालाँकि डिजिटल शिक्षा के अनेक लाभ हैं, फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की कमी, डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव आज भी



डॉ अंकुर सहाय श्रीवास्तव

गंभीर समस्याएँ हैं। यदि इन चुनौतियों का समय रहते समाधान किया जाए, तो डिजिटल शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंच सकती है।

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शिक्षा को और अधिक व्यक्तिगत, रोचक तथा परिणामोन्मुख बनाएँगी। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार किया जाए, शिक्षकों को नियमित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तथा विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित की जाए।

डिजिटल शिक्षा केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि ज्ञान, अवसर और सामाजिक समानता का एक सशक्त माध्यम है। यदि सरकार, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मिलकर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करें, तो भारत ज्ञान-आधारित, तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है।

- आजमगढ़





मुख्य अतिथि
श्री विश्वात्मा
संस्थापक/चेयरमैन- विश्व परिवर्तन मिशन
☎ 9811305324

अखिल भारतीय ओबीसी महासभा
एससी/एसटी संयुक्त मोर्चा
(किसान सेना)
के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

एक दिवसीय लीडरशिप ट्रेनिंग

सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण

राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललित कुमार गौर
विशेष अतिथि
किसान सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष
राधेश्याम मीणा श्याम पटेल
विशेष अतिथि

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अजय सिंह
विशेष अतिथि
प्रदेश अध्यक्ष-किसान सेना
डॉ कन्हैयालाल भारतीय
अध्यक्षता

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
एड. तुलसीराम पटेल साहव
विशेष अतिथि
जिला अध्यक्ष (पत्रकार)
कमल सिंह दांगी
मंच संचालन

**दिनांक :**
20 सितम्बर 2026

**स्थान :**
दागीं समाज धर्मशाला, जीरापुर, राजगढ़, म. प्र

**समय :**
सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक

साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा में हिंदी लाओ, देश बचाओ कार्यक्रम का शुभारंभ

श्रीनाथद्वारा से निर्दलीय के लिए उमेश पाठक कासगंज / श्रीनाथद्वारा। साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा के तत्वावधान में हिंदी लाओ, देश बचाओ समारोह के उद्घाटन सत्र का आयोजन श्री भगवती प्रसाद देवपुरा प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चण्डीगढ़ से पधारे हिंदी के विद्वान लेखक एवं आलोचक डॉ. अमर सिंह बधान उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. अमर सिंह बधान ने कहा कि हिंदी भाषा आज आमजन की भाषा है। यह भाषा आज समाज को दिशा निर्देशित करने वाली भाषा रही है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जैसे रचनाकारों ने इसी भाषा के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन शर्मा ने कहा कि भाषा की सेवा करना बहुत कठिन है। भाषा से संस्कृति जीवित रहती है, क्योंकि भाषा हमारी सोच और हमारे जीवन जीने की शैली का नाम है। यदि भाषा नहीं होगी तो अस्तित्व मिट जाएगा। उन्होंने साहित्य मंडल एवं श्री श्याम देवपुरा जी के कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि साहित्य मंडल आज आंग्ल भाषा की कुसंगतियों की आंधी में हिंदी के दीपक को बुझने से बचाने वाला वह हाथ है, जो संपूर्ण भारत को हिंदी से प्रकाशित कर रहा है।

कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि दिल्ली से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राहुल ने साहित्य मंडल एवं कनिष्ठ बाबूजी श्री भगवती प्रसाद देवपुरा जी के व्यक्तित्व को समाहित करते हुए कहा कि साहित्य मंडल ने हिंदी भाषा की ध्वजा को भारतवर्ष में लहराया है। आज देश के हर क्षेत्र के भाषाई व्यक्तित्व साहित्य मंडल में हिंदी भाषा का गुणगान करने के लिए प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैं। यही साहित्य मंडल के साथ-साथ हिंदी की समृद्धि है। इस हिंदी की ताकत है।

उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रिका उत्तर प्रदेश के संपादक डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ साहित्यकार कथाकार एवं आलोचक श्री गोपाल कृष्ण हांडा एवं एम.एल. चतुर्वेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा के साहित्यकार डॉ. अजीत रावत ने गणेश वंदना, भरतपुर के कवि हरि ओम



हरि ने सरस्वती वंदना, अलवर के कवि नानक चंद नवीन ने श्रीनाथ वंदना, भरतपुर के गीतकार नरेंद्र निर्मल एवं गौरव देवपुरा ने हिंदी गीत एवं कविता एवं राष्ट्रभाषा गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

इस अवसर पर देश के विविध देशों से पधारे हुए साहित्यकार एवं रचनाकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोयंबटूर तमिलनाडु के साहित्यकार संतोष कुमार आर. जे. जमी एवं जीवनलाल अग्निहोत्री स्मृति सम्मान एवं 5100 की राशि एवं साहित्य मर्मज्ञ की उपाधि से अभिवादित किया गया। सोरों उत्तर प्रदेश से पधारे श्री उमेश पाठक को ब्रजकांत साहित्य सम्मान एवं 5100 रुपए की राशि एवं ब्रज कांत साहित्य सम्मान की उपाधि, उपाधि पत्र, श्रीनाथजी की छवि, श्रीनाथजी का प्रसाद मेवाड़ी पगड़ी, शॉल, उत्तरीय, श्रीफल एवं कंठाहार से अभिवादित किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली भारत से प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र, झांसी, उत्तर प्रदेश के प्रा. फेसर मुन्ना तिवारी को श्री भगवती प्रसाद देवपुरा स्मृति सम्मान, डॉ. ए. अनुराधा, वेंकटरावपेट तेलंगाना को सोहनी देवी गिलड़ा स्मृति सम्मान, डॉ. सुरेश कुमार मिश्र उरतुस

हैदराबाद तेलंगाना को डॉ. दारक दयाल गुप्ता स्मृति सम्मान, डॉ. कुमुद वाला हैदराबाद तेलंगाना को श्रीमती सुरज केसरी फरक्या स्मृति सम्मान, डॉ. शशिकांत मिश्र जम्मू कश्मीर को श्री रामस्वरूप सिंगल स्मृति सम्मान एवं आर. सी. देवी, चेन्नई तमिलनाडु एवं डॉ. मंजू रुस्तगी चेन्नई तमिलनाडु को श्री रामस्वरूप आर. वाल स्मृति सम्मान एवं 3100 रुपए की राशि एवं हिंदी भाषा शिरोमणि की मानद उपाधि से अभिवादित किया गया। इस अवसर पर तीन पुस्तकों डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कृत फलौपधियां कुण्डलिया, रविंद्र नाथ तिवारी कृत राष्ट्रीय चिंतन, हरिओम शर्मा हरी कृत लहरों से सीखा नौका ने एवं मासिक पत्रिका द अंडरलाइन का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर चेन्नई तमिलनाडु की आर. श्रीदेवी वेंक. टरावपेट, तेलंगाना की डॉ. एम. अनुराधा, जम्मू कश्मीर के डॉ. शशिकांत मिश्र एवं हैदराबाद तेलंगाना के डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतुस ने हिंदी उपनिषद एवं सुरेश कुमार शर्मा भरतपुर, नानक चंद शर्मा नवीन एवं नरेंद्र निर्मल भरतपुर में हिंदी हुकृति का पाठ किया। संस्थान के प्रधानमंत्री श्याम प्रकाश देवपुरा ने

सभी का अतिथियों और साहित्यकारों का स्वागत सम्मान किया।

इसी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के तीर्थ नगरी शूकरक्षेत्र क्षेत्र सोरों जी से आये वरिष्ठ उद्घोषक आकाश वाणी से से. नि. डा. श्रीकृष्ण शरद, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) शाखा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव एवं प्रधान संपादक पवित्र विचारसोरों टाइम्स विक्रम पाण्डेय, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश शाखा कासगंज के जिलाध्यक्ष मनोज पाराशर एवं जिला सचिव अजेन्द्र शर्मा ने साहित्य मंडल के प्रधान मंत्री श्याम प्रकाश देवपुरा को भगवान वराह का छविचित्र व पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग सौ साहित्यकार, कवि एवं लेखक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री श्री श्याम देवपुरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सम्मानित साहित्यकारों का गद्यात्मक एवं पद्यात्मक परिचय भरतपुर के कवि हरिओम हरि, एवं भरतपुर के श्री नरेंद्र निर्मल ने किया।

आत्मविश्वास का साथ आत्मनिर्भरता की राह



1.25 करोड़+ लाड़ली बहनों को
₹1835 करोड़+
का अंतरण

मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव
द्वारा

विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण

13 सितम्बर, 2026 । आगर मालवा, मध्यप्रदेश

D-11111/26

आकल्पन : मा.प्र. माध्यम / 2026

अब तक

लाड़ली बहनों को

₹65,300 करोड़+
की सहायता का अंतरण



सीधा प्रसारण

Webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

jansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी